



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54954

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2521/2026

भूपेन्द्र सिंह

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अमर जीत सिंह, भुवनेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भुवनेश कुमार सिंह और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मोर्य को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 616/2018 धारा 420, 406, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता थाना धामपुर, जिला बिजनौर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जांच के दौरान अपीलार्थी को धारा 41-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस तामील किया गया था और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आगे यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी को कभी भी समन, जमानती वारंट या गैर-जमानती वारंट तामील नहीं किया गया है और अब उसके खिलाफ धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया जारी की गई है। अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है।
6. अपीलार्थी को जांच के दौरान धारा 41-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस तामील किया गया था और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अपीलार्थी को कभी भी समन, जमानती वारंट या गैर-जमानती वारंट तामील नहीं किया गया है और अब उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोप की प्रकृति, अपीलार्थी की भूमिका और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य आपराधिक अपील संख्या 4564/2024** के फैसले को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अपीलार्थी **भूपेंद्र सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और कोई अनुचित स्थगन नहीं मांगेगा;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

वंदना